हरिभूमि पेज 2
1.3.14

सिब्बल ने स्वीकारा, सरकारी नीतियां जमीनी हकीकत से परे

हरिभूमि न्यूज. नई दिल्ली

लोकसभा चुनावों के आते ही केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल को अब सरकारी नीतियों व जमीनी हकीकत में भारी अंतर नजर आ रहा है। उनको नजर में व्यापारियों के आक्रोश की मुख्य जड़ यही है। चलो देर से ही सही कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री ने माना तो सही कि व्यापारियों को लेकर सरकार की नीतियां जमीनी हकीकत से परे है। कपिल सिब्बल शुक्रवार को सिविक सेंटर में आयोजित कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी महाधिवेशन के दूसरे दिन बोल रहे थे। इससे ठीक एक दिन पहले भाजपा के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने महाधिवेशन में व्यापारियों को संबोधित किया था।

■ गलत नीतियां ही हैं व्यापारियों के आक्रोश का कारण

सिब्बल ने व्यापारियों को भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत रीड की हड्डी बताते हुए कहा की यदि देश में व्यापारियों को व्यापार करने के सुलभ रास्ते उपलब्ध नहीं कराए तो अर्थव्यवस्था कतई मजबूत नहीं हो सकती। देश के आंतरिक व्यापारिक ढांचे को मजबूत करने के लिए व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय व्यापारी नीति बनाई जानी बेहद जरूरी है और केंद्र सरकार में तथा देश के सभी राज्यों में एक ट्रेड बोर्ड बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा की यह दुर्भाग्य की बात है की सरकारी नीतियां जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके बनती है और इसलिए ही व्यापारियों में आक्रोश रहता है। व्यापारी मुद्दों पर नीति बनाने से पहले व्यापारियों से परामर्श किया जाना बेहद जरूरी है।

दैनिक जागरण पेज 17
1.3.14

व्यवसायियों ने कर नीतियों पर जताया रोष

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : निगम मुख्यालय सिविक सेंटर के कन्वेंशन हॉल में व्यवसायियों के जिस सम्मेलन में मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल थे, उस सम्मेलन में उनके आने से पहले से लेकर उनके जाने के बाद तक देश भर से आए अधिकतर व्यवसायी केंद्र सरकार पर ही भड़ास निकालते रहे। व्यवसायियों का दर्द भारी भरकम कर, सरकार की नीतियों, भ्रष्टाचार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को लेकर अधिक था। व्यवसायियों का कहना था कि प्रशासन में हर स्तर पर उनका शोषण होता है। जबकि यही वर्ग सरकार के लिए टैक्स कलेक्टर (कर संग्रहणकर्ता) है।

व्यवसायियों की समस्याओं पर चर्चा के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा बुलाए गए इस सम्मेलन में दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब व जम्मू कश्मीर आदि से व्यवसायी शामिल हुए। सम्मेलन में व्यवसायियों ने एक सुर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2005 को काला कानून बताया। केंद्र सरकार ने देश भर में हो रहे विरोध के चलते इसे अभी तक लागू नहीं किया है। व्यवसायियों ने कहा कि यह कानून लागू होगा तो उन्हें बेवजह जुर्माना भरना होगा और जेल जाना होगा।

सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे सिब्बल की व्यवसायियों ने यह कह कर तारीफ की कि केंद्र सरकार में कपिल सिब्बल के एक ही व्यक्ति हैं जो हर समय उनकी मदद करते हैं। मगर केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर नाराजगी दिखाई। व्यवसायियों ने सिब्बल को मांगपत्र सौंपा जिनमें उनसे कहा गया कि खाद्य सुरक्षा कानून पर व्यवसायी केंद्र और राज्य सरकार के बीच घूम रहा है।

...सिब्बल बोल गए विपक्ष में बैठने की बात

सिविक सेंटर में कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा आयोजित सम्मेलन में शुक्रवार को पहुंचे कपिल सिब्बल अपने भाषण में बोल गए कि चुनाव जीते और सरकार आई तो सत्ता में रह कर आप सब की मदद करेंगे। यदि विपक्ष में बैठना हुआ तो विपक्ष में रहकर आपकी बातों को उठाएंगे। यदि विपक्ष भी नहीं मिला तो वकालत कर आपकी मदद करेंगे। मगर मदद हर समय करेंगे। यह बात सिब्बल ने बेहद हल्के मूड में कही, मगर सम्मेलन में माहौल एकदम शांत हो गया।

नवोदय टाइम्स पेज 13
1.3.14

देश की प्रगति व्यापार बढ़ने से : सिब्बल

नई दिल्ली, 28 फरवरी (एजेंसी):

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि देश तभी प्रगति करेगा जब व्यापार बढ़ेगा।

व्यापारियों के संगठन 'अखिल भारतीय व्यापार परिसंघ' (सी.ए.आई.टी.) के एक कार्यक्रम में सिब्बल ने कहा कि वह पूरी तरह व्यापारियों के साथ हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में वह हारें या जीतें व्यापारियों की वकालत करते रहेंगे। सिब्बल ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नीति बनाए जाने की परिसंघ की मांग का समर्थन किया लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) पर उनके विरोध पर कहा कि उनका मत इससे अलग है।

उन्होंने कहा कि यदि भारतीय व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिता में बने रहना है तो हमें अपने व्यापार का स्तर बढ़ाना होगा और इसके लिए बाजार में दूसरे विकल्प उपलब्ध होने से मदद ही मिलेगी।

कानून मंत्री ने माना कि भारतीय व्यापारियों के सामने कई चुनौतियां हैं। यहां ऋण 10 से 12 प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलता है जबकि विदेशों में यह 1 से 2 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध है। साथ ही देश में बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किए जाने की जरूरत है।

जल्द लांच हो सकता है ई-व्यापार

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अखिल भारतीय व्यापार परिसंघ (सी.ए.आई.टी.) द्वारा मिलकर तैयार की जा रही ई-व्यापार परियोजना का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही लांच किया जा सकता है।

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने बताया कि इससे देश के एक कोने में बैठा व्यापारी सिर्फ उसी जगह तक सीमित नहीं रहेगा। वह सैंकड़ों मील दूर बैठे ग्राहक को भी अपना सामान बेच सकता है।

उन्होंने कहा कि इससे ग्राहकों के पास भी कई विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे और वह इंटरनैट पर सामान की कीमत और उसकी गुणवत्ता देखने के बाद तुलना कर खरीदने के लिए आर्डर दे सकते हैं। परियोजना का साफ्टवेयर लगभग तैयार हो चुका है और इसे 10 से 15 दिनों के भीतर लांच किया जा सकता है।

Mail Today P 10

1.3.14

Sibal urges traders to embrace FDI

A DAY after BJP's PM nominee Narendra Modi exhorted traders to fight global challenges, Telecom Minister Kapil Sibal (inset) said the country needs a national trade policy to help retailers compete globally.

Speaking at an event organised by the Confederation of All India Traders (CAIT), Sibal said the government wanted traders to compete and expand for which they need infrastructure and facility as available abroad.

Claiming that FDI would help traders grow their scale of business, like the way it happened in the automobile sector, Sibal said: "When we changed our policy on automobiles we had only two cars companies, FIAT and Hindustan Motors. There were concerns about these two companies. Then we brought Maruti and today we make cars here. Indian automobile component makers are supplying parts to global car companies abroad. We have to adopt a similar thought. I am in favour of FDI."

The BJP, meanwhile, challenged the Congress to an open debate on the economic vision adopted to revive the country's sagging economy.

Mail Today/New Delhi

Asian Age P 3
1.3.14

Union communications & IT minister Kapil Sibal at a traders national summit in New Delhi on Friday. — PTI

बिजनेस भास्कर पेज 6
1.3.14

मोदी का नया स्टैंड

अर्थव्यवस्था के हित में नहीं नीतियों में दोहरापन

मोदी ने रिटेल एफडीआई और जीएसटी का समर्थन किया है जबकि विरोधाभास यह है कि भाजपा अभी तक इनके खिलाफ रही है

संसदीय व्यवस्था में मजबूत विपक्ष का होना स्वस्थ माना जाता है। लेकिन विपक्ष का मतलब सरकार की सभी नीतियों का विरोध नहीं होना चाहिए। अफसोस कि अपने देश में यह स्वस्थ परंपरा अभी तक नहीं पनप सकी है। कल तक रिटेल में विदेशी निवेश और जीएसटी के खिलाफ बोलने वाली भाजपा के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने इन दोनों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि छोटे कारोबारियों को विदेशी निवेश का विरोध करने के बजाय खुद को ग्लोबल चुनौतियों का सामना करने लायक बनाना चाहिए, उत्पादों की क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। अभी तक भाजपा विदेशी सुपरमार्केट्स के खिलाफ रही है। पार्टी बार-बार कहती रही है कि ये करोड़ों किराना दुकानों के लिए खतरा हैं। करीब महीने भर पहले ही राजस्थान में भाजपा की वसुंधरा सरकार ने मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई के समर्थन के पूर्ववर्ती गहलोत सरकार का फैसला पलट दिया। मोदी कहते हैं विदेशी निवेश की बाधाएं दूर करना और माहौल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। यही रवैया जीएसटी पर है। जगजाहिर है कि बीजेपी शासित राज्यों के विरोध के कारण ही अभी तक जीएसटी लागू नहीं हो सका है। लेकिन अब मोदी कह रहे हैं कि इससे बिजनेस की लागत घटेगी। मतलब है कि भाजपा मुद्दों का इसलिए विरोध कर रही थी कि क्योंकि वह विपक्ष में थी। नीतियों में दोहरापन नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई भी निवेशक पांच-दस साल के लिए पैसे नहीं लगा सकता। अगर आमचुनाव के बाद कांग्रेस के सिर विपक्ष का सेहरा बंधता है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि इन मुद्दों पर उसका रवैया क्या रहता है।

बिजनेस भास्कर पेज 2
1.3.14

व्यापारियों को नसीहत...

नई दिल्ली में ट्रेडर्स कांग्रेस को सम्बोधित करते केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल। फोटो : संजय गुप्ता

बिजनेस स्टैंडर्ड पेज 5
1.3.14

रुख में बदलाव

यह बात तो सबको पता है कि कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और ई कॉमर्स का कट्टर विरोधी रहा है। लेकिन गुरुवार को जब संगठन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी की मेजबानी की तो ऐसा लगा कि वह इन दोनों ही मोर्चों पर अपनी शंकाओं से पूरी तरह निजात पा चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि संगठन में उस शाम के सितारा वक्ता रहे मोदी को एफडीआइ और ई-कॉमर्स का कट्टर हिमायती माना जाता है। इतना ही नहीं सीएआईटी में आयोजित उस समारोह के प्रमुख प्रायोजकों में से एक ईबे इंडिया भी थी।